REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331 (UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 7 | APRIL - 2018

कैसे पुरा होगा शिक्षित भारत का सपना तोता रटंत शिक्षा से ?

अपराजिता कुमारी
बी.एड. एम.एड. एम0ए0 (शिक्षा)

प्रस्तावना :

शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं–

भारत में उपनिषदों बलिक उससे भी प्राचीनकाल से शिक्षा और ज्ञान के प्रतिष्ठित केन्द्रों के रूप में विख्यात रही हैं। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय मात्रा धार्मिक शिक्षा के ही नहीं बल्कि विज्ञान, खगोल, चिकित्सा तथा दर्शन जैसे विविध क्षेत्राों में व्यवहारिक शिक्षा के लिए विख्यात रहे हैं। मिथिला और नाडिया की भारतीय दर्शन की न्याय शाखा के प्रमुख केन्द्रों के रूप में प्रतिष्ठ रही हैं।

मध्यकाल में भी देश में अनेक मकवन और मदरसे ऐसी शिक्षा प्रदान कर रहे थे जो किसी भी मानदण्ड से उत्कृष्ट ही कही जा सकती हैं।

आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्रो में पर्याप्त विस्तार हुआ हैं, लेकिन शिक्षा की प्रगति पर यदि दृष्टि डाले तो पता चलता है कि वृद्धि संख्यात्मक रूप से उल्लेखनीय हैं, किन्तु गुणात्मक रूप से इसमें ह्रास हुआ हैं।

देश की शिक्षा को उसके भविष्य के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हम जैसी शिक्षा अपनी वर्त्तमान पीढ़ी को प्रदान करेंगे वैसा ही उसका भविष्य भी होगा।

शिक्षा में तेजी ने तथा बेहतर करने की इच्छा ने एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर दी हैं।

शिक्षा का उद्देश्य क्या हैं ? हम अपने स्कूलों के जरिये कैसा इंसान तैयार करना चाहते हैं ? एक शिक्षित व्यक्ति का समझ और दुनियाँ से कैसा संबंध होना चाहिए ? ऐसा लगता है कि आधुनिक शैक्षिक प्रणाली में मुख्य जोर टेक्नोलॉजी और किताबी ज्ञान से संपन्न भद्रलोगों वाले **(टेक्नोक्रेटिक – मेरिटोक्रेटिक)** वैश्विक परिदृश्य का निर्माण करना मात्र है। यह प्रणाली तथाकथित शिक्षितों का ऐसा वर्ग तैयार करना चाहती हैं जो जिज्ञासा न करें, बताये गए को बिना सोचे समझे, स्वीकार कर ले जानने के बजाय समझौता कर लें। स्वाभाविक हैं कि ऐसे महौल में दास मानसिकता फल–फुल रही हैं और आत्मिक शक्ति तथा जीवन मूल्यों के प्रति निर्भिक प्रतिबद्धता बिरल होती जा रही हैं।

आज शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अच्छा इंसान बनना नहीं बल्कि अच्छा वेतन पाना मात्रा रह गया हैं। ज्ञान और उत्पादक कार्य के बीच गहरी खाई बनी हुई हैं। शिक्षा पूँजी के हितग्राही हो गई हैं और ऐसे वर्ग को जन्म दे रही हैं, जो विचार और कार्य में पूँजी का मददगार हों। बाजार में शिक्षा को मुनाफे का माध्यम बना लिया शिक्षा जन सरोकारों की अपेक्षा धन सरोकारों से जुड़ गई हैं। स्कूल शिक्षा की दुकान और विद्यार्थी उपभोक्ता में बदल गए हैं। जिसके पास जितने आर्थिक संसाधन हैं वह वैसी शिक्षा खरीद रहा हैं। कम पैसे वालों के लिए एक तरह की शिक्षा और अधिक पैसों वालों के लिए दूसरे तरह की शिक्षा जिसकी आर्थिक हैसियत जैसी हैं वैसी शिक्षा खरीद लें, यह शिक्षा बाजार का घोषित ऐलान हैं। ट्यूशन या कोचिंग नये धंधे के रूप में अस्तित्व में आये हैं। अखबारों के बड़े–बड़े विज्ञापन देकर इनसे जुड़े संस्थान विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

कुंजी और गाइड छापने वालों का धंधा खूब फल–फूल रहा हैं। सभी का जोर एक ही बिन्दु पर हैं कि कैसे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं ? सभी यहीन तरकीब बताने में लगे हुए हैं। बच्चों को साँस लेने की फुरसत नहीं हैं। एक अंधी दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं जो सफल हो गए वे अपने आप को सिकन्दर समझ रहे हैं और जो पीछे रह जा रहे हैं। वे कुंठा, तनाव तथा अवसाद से ग्रस्त हो आत्महत्या कर रहे हैं या

मानसिक संतुलन खो रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत की गिद्ध दृष्टि शिक्षा के व्यवसाय पर लगी हुई है। हो भी क्यों न इससे उसे दोहरा लाभ हैं। पहला, शिक्षा में बार–बार निवेश किए बिना दीर्घकाल तक धन प्राप्ति। दूसरा, शिक्षा में नियंत्राण के द्वारा नयी पीढ़ी की मानसिकता को बाजार के अनुकूल कर अपने बाजार का निर्बाध रूप से विस्तार करना। आज शिक्षा में मूल्यों की बात केवल कहने भर के लिए रह गई हैं। मानती मूल्य हाथी के दांत हो चुके हैं। सामाजिक न्याय जैसे शब्द सजावट के शब्द बन गए हैं। बाजार में बिक रही शिक्षा का मूल्यों से कुछ लेना देना ही नहीं हैं। यह विशुद्ध रूप से बाजार के अनुकूल शिक्षा है। इसका उद्देश्य अर्थ मानव तथा व्यवस्था की मशीन में फिट होने वाले पूर्जे तैयार करना हैं। शिक्षा की दुकानों में वही शिक्षा बेची जा रही जिसकी कॉरपोरेट जगत को जरूरत हैं। बाजार को ऐसा मानव संसाधन चाहिए जो उसकी कंपनियों में लगी अत्याधुनिक तकनीक की मशीनों को सही ढंग से परिचालितकर सके। ऐसे उत्पादों को खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मानसिक रूप से तैयार कर सके। ऐसे उत्पादों को भी बेच सके जो उपभोक्ता की आवश्यक आवश्यकता न हो। बाजार सोचने समझने वाला संवेदनशील मानव नहीं चाहता। ऐसा मानव उसके किसी काम का नहीं। इसलिए आज की शिक्षा एक कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक या प्रशासक तो तैयार कर रही हैं पर उसे एक संवेदनशील इंसान नहीं बना रही हैं। न ही यह शिक्षा सृजनशीलता के अवसर पर बाजारवादी शिक्षा ने निगल लिए हैं। इस शिक्षा में ऐसी क्षमता नहीं है कि यहकिसी की साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक या चिंतक बना सके। यह उसकी न मंशा हैं और न ही जरूरत। दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि हमारी लोकल्याणकारी, समाजवादी तथा लोकतांत्रिाक सरकारें इसी शिक्षा की पैरोकार है आजादी के बाद से लेकर आज तक चल रही दोहरी शिक्षा को आज बहुपरती शिक्षा में बदल गई हैं।

इसी का परिणाम हैं नीति आयोग में जनता के पैसों से विद्यालयों का आधारभूत ढाँचा विकसित कर प्रबंधन के नाम पर निजी हाथों को देने की योजना बना चुकी है। शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 ने तो रही सही कसर पुरी कर दी है। इन अधिनियम में ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो शिक्षा के निजीकरण को खुला प्रोत्साहन देते हैं। निजी स्कूल में 25 प्रतिशत गरीब वंचित तबके के बच्चों को वाउचर प्रदान कर भेजने की योजना से निर्धन और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित हो जाने के प्रावधान वे अमीर और गरीब वर्ग के बीच खाई बाँटने में सहायता मिलेगी। अब रिक्शा चालकों, सफाई कर्मियों, ठेले वालों, मजदूरों आदि के बच्चे साहेब और सेठ–साहुकारों के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ेंगे लेकिन तीन वर्ष के अनुभव बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा होने के स्थान पर बच्चों की एक कटेगरी (वाउचर वाले बच्चे) बन गया। निजी विद्यालयों ने वाउचर वाले बच्चों के लिए एक तोड़ निकाल लिया हैं, उन्होंने ऐसे बच्चों की एक अलग कक्षा बना दी हैं। यहाँ ऐसे बच्चे केवल हीनता ग्रंथि के शिकार हो रहे हैं। उससे अधिक उनको कुछ मिलने वाला नहीं हैं। इस प्रावधान से आने वाले समय में सरकारें नये विद्यालय खोलने के अपने दायित्व से बच जायेगी। साथ ही इन मान्यता को भी अधिक बल मिलेगा कि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से बेहतर होते हैं। कैसी विडंबना हैं कि सरकार को अपने ही विद्यालयों पर विश्वास नहीं रह गया हैं। सरकार सरकारी स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने की अपेक्षा जनता को निजी विद्यालयों की ओर जाने को प्रोत्साहन कर रही हैं। होना तो यह चाहिए था कि सरकार को अपने बीमार विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उस ओर आकर्षित करती।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार धीरे–धीरे शिक्षा को निजी क्षेत्रा के भरोसे छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं। आज सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चे ही आ रहे हैं और जिस दिन ये बच्चे भी वाउचर लेकर निजी स्कूलों में चले जाऐंगे तब फिर सरकारी स्कूलों को बंद करने के सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं रहेगा। जैसा कि यह सिलसिला शुरू भी हो गया है। इस तरह एक दिन शिक्षा पूरी तरह निजी हाथों में चली जाएगी और देशी विदेशी व्यापारी शुद्ध लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएँ संचालित करने लगेंगे। सोचा जा सकता है तब शिक्षा का उद्देश्य क्या रह जाएगा ? शिक्षा मूल्यों की बात रह जाएगी और कितनी जीवन की ?

वर्त्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन सही रूप में नहीं होने के कारण शिक्षा के कमजोरियों के लिए आर्थिक मजबूरियों को दोषी माना जाता हैं। उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों की उतनी कमी नहीं हैं जितनी कि अच्छे प्रबंधन की हैं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में चाहे जितना खर्च कर लें तब तक सुधार संभव नहीं होगा जब तक अच्छे प्रबंधन पर जोर नहीं दिया जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय तथा ज्ञान विज्ञान में अधिकतम नेतृत्व करना तथा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करना और जीवन को सांस्कृतिक रूप से सबद्ध करना हैं। अर्थात् यदि किसी राष्ट्र के मानवीय संसाधनों के त्वरित

विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता तो वह राष्ट्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्राों में भी समुचित विकास नहीं कर पाता हैं। मानवीय संसाधनों के ज्ञान, कुशलता, क्षमता और दक्षता में वृद्धि शिक्षा के द्वारा ही संभव होती हैं परन्तु दुखद बात यह है कि आज भवन और भौतिक संरचना को अधिक महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और सभी समस्या के हल में धन को देखा जाता है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्याओं को देखकर लोगों ने जगह–जगह नये कॉलेज खोले हैं जब उनमें प्रवेश की समस्या हल नहीं हो पाती तो पत्राचार माध्यम से डिक्यिाँ थोक में प्रदान की जाती हैं और सभी नियमों का उल्लंघन कर ताक पर रख दिये जाते हैं।

कितने अफसोस की बात हैं कि समान शिक्षा के लिए आजादी से अब तक संसद से लेकर शिक्षा संबंधी विभिन्न दस्तावेजों में अनेकानेक बार संकल्प व्यक्त किया जा चुका है लेकिन धरातल में कहीं समान शिक्षा नहीं दिखाई देती हैं।

सबका शिक्षा और शिक्षित भारत का सपना गुणवत्ता से जुड़ा हुआ हो यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती हैं तो ऐसा शिक्षा का दिया जाना किसी मतलब का नहीं हैं। शिक्षक छात्रा का जो मौजूदा अनुपात 1 : 30 तय किया गया हैं। उसमें कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त , यह समझा जा सकता है। एक शिक्षक द्वारा एक भवन में एक से अधिक कक्षाओं और स्तरों के बच्चों को पढ़ाने से बच्चों को शिक्षा नहीं सरकारी प्रमाण–पत्रा ही दिया जा सकता है।

प्रख्यात शिक्षाविद् अनिल सदगोपाल का मानना भी हैं। शिक्षा जरिये वर्ग–भेद, जाति–भेद, धार्मिक कट्टरता, नस्लवाद, पित्रासत्ता, सामंती व गैर–तार्किक सोच, पिछड़ेपन आदि विकृतियों के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़ाने के सरोकार गौण हो रहे हैं। शिक्षा वैश्विक बाजार की ताकतों के हाथों में वर्चस्ववाद, शोषण, सांप्रदायिकता व विषमता फैलाने का हथियार बनती जा रही है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न तो परियोजनाओं से और न ही सार्वजनिक निजी भागीदारी मंडल से शिक्षा का भला हो सकता है। इसके लिए तो एक स्थायी और मजबूत सार्वजनिक ढांचा खड़ा करने की जरूरत है। अन्यथा सबको शिक्षा समानशिक्षा और शिक्षित भारत का सपना केवल स्वप्न मात्रा बनकर रह जायेगा। इस दिशा में गंभीरता पूर्वक विचार कर ईमानदारी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1 एन्शियण्ट इण्डियन एजुकेशन राधा कुमुद मुखर्जी।
2 एजुकेशन इन एन्शियण्ट इण्डिया ए.एस अल्लेकर।
3 लर्निंग : द ट्रेजर विदिन युनेस्कोप पब्लिशिंग पेरिस 1996।
4. योजना।
5. प्रतियोगिता दर्पण।
6. एजुयोगिता शुड एम. फोर्ड सोशल कोहेशन्।
7. रिलिजियस अमटी जे एस राजपुत न्यू इंडियन एक्सप्रेस।
8. भतृहिरि शतकत्रयी
9. केस फॉर इंडिया, विल डयूरन्ट

अपराजिता कुमारी
बी.एड. एम.एड. एम0ए0 (शिक्षा)